संख्या-1/2026/141/94-1-2026-312(206)/2025

प्रेषक,

अमित गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 23 जनवरी, 2026**

विषय : स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अनावासीय कार्यालय (विभागीय) भवनों के आगणन प्रस्ताव के दृष्टिगत निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान/ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-249/भवन-2/शि0का0लख0/2025-26 दिनांक 16.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद कौशाम्बी में उप निबन्धक कार्यालय, मंझनपुर, सिराथू एवं चायल के नवनिर्माण हेतु आगणित कुल लागत धनराशि रु० 686.85 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के अन्तर्गत धनराशि रु० 343.425 लाख की स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में कुल लागत रु० 686.85 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में पचास प्रतिशत धनराशि रु० 343.425 लाख (रुपये तीन करोड़ तिरालीस लाख बयालीस हजार पाँच सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा निम्नांकित कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका

क्र० सं०	जनपद का नाम/ कार्यदायी संस्था	स्थल का नाम	निर्माण हेतु प्रस्तावित भवन का प्रकार	भवन की मानकीकृत लागत/ आगणन (लाख में)	प्रथम किश्त हेतु निर्गत की जाने वाली रु० लाख में।
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**कौशाम्बी** /उ०प्र० राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०।	मंझनपुर	कार्यालय उप निबन्धक, मंझनपुर	228.95	114.475
		सिराथू	कार्यालय उप निबन्धक, सिराथू	228.95	114.475
		चायल	कार्यालय उप निबन्धक, चायल	228.95	114.475
				686.85	**343.425**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025, संख्या-5/2024/बी-1-642/दस-2024-231/2024, दिनांक 16.07.2024 व समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. निर्माण हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त प्रक्रिया एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जायेगा।
4. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद में किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
6. कार्यदायी संस्थाओं को कार्य की गुणवत्ता एवं कार्यालय भवन निर्माण हेतु तय समय-सीमा (धनावंटन के पश्चात यथा संम्भव 06 माह के भीतर) में किसी प्रकार का विचलन अनुमन्य नहीं होगा।
7. निर्माण कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित कराने हेतु महानिरीक्षक निबंधन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
8. निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। परियोजना के क्रियान्वयन में टाईम ओवर रन, कॉस्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चत किया जायेगा।
9. कार्यों की द्विरावृत्ति/ पुनरावृत्ति न हो इसे महानिरीक्षक निबन्धन द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
10. धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
11. नियमानुसार समस्त यथा आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही परियोजना निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
12. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
13. कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण हो जाये।
14. प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाय तथा कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रत्येक दशा में निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
15. कार्यदायी संस्था द्वारा सेंटेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबंधन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023 /ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17.05.2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/ दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19.05.2023 में निहित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रु० 343.425 लाख (रुपये तीन करोड़ तिरालीस लाख बयालीस हजार पाँच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-091 लेखा शीर्षक-4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-कार्यालय भवन, 800-अन्य व्यय, 03 स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग के कार्यालय भवनों के निर्माण, 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
5. प्रबंध निदेशक, उ०प्र०, राज्य निर्माण सहकारी संघ लि०।
6. जिलाधिकारी, कौशाम्बी।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
8. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
9. उप महानिरीक्षक निबंधन/ उपायुक्त स्टाम्प, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
10. सहायक महानिरीक्षक निबंधन, कौशाम्बी।
11. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
13. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।